

MPS-003 IMPORTANT QUESTIONS

तेभागा आंदोलन:

तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल (अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल) में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमींदारों द्वारा किसानों से लिए जाने वाले हिस्से को कम करके दो-तिहाई (तेभागा) करना था। किसानों को पहले अपनी फसल का आधा हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था, लेकिन इस आंदोलन के तहत उनकी मांग थी कि उन्हें सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही देना पड़े।

The Tebhaga Movement was a significant peasant movement in Bengal (now Bangladesh and West Bengal) during 1946-47. The primary objective of this movement was to reduce the share of the crop that landlords took from the farmers to one-third (tebhaga). Previously, farmers had to give half of their crop to the landlords, but the movement demanded that they only need to give one-third.

इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और किसान सभा ने किया। आंदोलन के दौरान, किसानों ने व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन और हड़तालें कीं। कई स्थानों पर यह आंदोलन हिंसक भी हो गया, जिसमें पुलिस और प्रशासन के साथ संघर्ष हुए।

The movement was led by the Communist Party of India (CPI) and the Kisan Sabha. During the movement, farmers engaged in widespread protests and strikes. In many places, the movement turned violent, resulting in clashes with the police and administration.

तेभागा आंदोलन का प्रभाव बंगाल के किसान आंदोलनों पर गहरा पड़ा। इस आंदोलन ने किसानों को संगठित किया और उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर

पर उठाया गया। इसके परिणामस्वरूप भूमि सुधारों के लिए कई नीतिगत परिवर्तन किए गए।

The Tebhaga Movement had a profound impact on peasant movements in Bengal. It organized the farmers and brought their issues to the national forefront. As a result, several policy changes were made regarding land reforms.

हालांकि तेभागा आंदोलन अपने सभी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सका, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया। इस आंदोलन ने किसानों के अधिकारों और उनके हकों की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।

Although the Tebhaga Movement did not achieve all its goals, it significantly highlighted the role of peasants in the Indian freedom struggle. The movement laid a strong foundation for the protection of farmers' rights and their entitlements.

FEDERAL SYSTEM IN INDIA

भारतीय संघीय प्रणाली संविधान द्वारा परिभाषित एक महत्वपूर्ण ढांचा है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करता है। संविधान के सातवें अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची के माध्यम से यह विभाजन स्पष्ट किया गया है।

The federal system in India is a significant framework defined by the Constitution, which delineates the division of powers between the

central and state governments. This division is explicitly outlined through the Union List, State List, and Concurrent List in the Seventh Schedule of the Constitution.

भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए कई संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। इनमें प्रमुख हैं - राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद और राज्य विधानसभाएं। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भी इस संतुलन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

In the Indian federal system, there are several institutional mechanisms to maintain a balance of power between the central and state governments. Key among these are the President, Governors, Parliament, and State Legislatures. Additionally, the Supreme Court and High Courts play a crucial role in ensuring this balance.

संविधान में संशोधन के माध्यम से समय-समय पर संघीय ढांचे में बदलाव किए गए हैं ताकि बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार इसे और प्रभावी बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

Through constitutional amendments, changes have been made to the federal structure from time to time to make it more effective according to changing times and circumstances. For example, the 73rd and 74th amendments provided constitutional status to Panchayati Raj institutions and urban local bodies.

भारतीय संघीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें आपातकालीन प्रावधान भी शामिल हैं, जिनके तहत केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारों के कार्यों का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है।

यह प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल के तहत आते हैं।

A significant feature of the Indian federal system is that it includes emergency provisions, under which the central government can take control of the functions of state governments in special circumstances. These provisions come under National Emergency, State Emergency, and Financial Emergency.

POLITICAL PARTICIPATION IN INDIA

भारतीय राजनीति में नागरिकों की भागीदारी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस भागीदारी के विभिन्न रूप हैं, जैसे मतदान, चुनाव में प्रत्याशी बनना, राजनीतिक दलों का सदस्य बनना, और विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेना। भारत में राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई संवैधानिक और कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

Citizen participation in Indian politics is a crucial aspect of democracy. This participation takes various forms, such as voting, running for elections, becoming a member of political parties, and participating in various political movements. Several constitutional and legal provisions have been made in India to promote political participation.

भारत में मतदान का अधिकार सभी वयस्क नागरिकों को दिया गया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

चुनावों में बढ़ती मतदान दर और युवाओं की भागीदारी भारतीय लोकतंत्र के सशक्तीकरण का प्रमाण है।

The right to vote in India is granted to all adult citizens, making it the most fundamental and significant part of the democratic process. The Election Commission of India is responsible for ensuring free and fair elections. Increasing voter turnout and the participation of young people in elections are testimonies to the strengthening of Indian democracy.

राजनीतिक दल भारतीय राजनीति में नागरिकों की भागीदारी के प्रमुख माध्यम हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों में शामिल होकर, नागरिक अपने विचारों और नीतियों को प्रकट कर सकते हैं और सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यह राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर लोगों की आवाज़ को मंच प्रदान करते हैं।

Political parties are the primary medium for citizen participation in Indian politics. By joining various political parties, citizens can express their ideas and policies and participate in the government's policy-making process. These political parties provide a platform for people to voice their concerns on various social, economic, and cultural issues.

विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन भी नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे आंदोलनों के माध्यम से लोग सरकार पर दबाव डाल सकते हैं और अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। हाल के वर्षों में, नागरिक समाज संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका भी बढ़ी है, जो सरकार की नीतियों और कार्यों पर नजर रखते हैं और आवश्यक सुधारों की मांग करते हैं।

Various social and political movements also serve as an essential medium for citizen political participation. Through these movements, people can put pressure on the government and get their demands met. In recent years, the role of civil society organizations and non-governmental organizations has also increased, which monitor government policies and actions and demand necessary reforms.

Scholarly Minds